at the first and second Conference of the Central and State Minorities Commissions for grant of Constitutional position or status by means of appropriate Constitutional amendment to the Central Minorities Commission. Government is not considering any proposal to confer Constitutional position or statutory status upon the Minorities Commission. Attention in this connection is also invited to reply given to Unstarred Question No. 1774 on the 25th November, 1988.

महाराष्ट्र में श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों में लम्बित श्रमिक विवाद

2833. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों में बड़ी संख्या में श्रमिक विवाद लम्बित पड़े हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र में श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों की कमी है जिसके परिणामस्वरूप निर्णय देने में विलम्ब होता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन विवादों को शीघ्र निपटाये जाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री विद्येश्वरी दुबे) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उस राज्य में 1-7-88 तक औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष 18334 मामले लम्बित थे और श्रम न्यायालयों में 58,930 मामले लम्बित थे।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में 19 औद्योगिक न्यायालय और 35 श्रम न्यायालय हैं। अतिरिक्त औद्योगिक न्यायालय और श्रम न्यायालय मंजूर करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। औद्योगिक न्यायालयों और श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि लम्बे समय से लम्बित मामलों को अग्रता दें और उन्हें शीघ्र निपटाएं।

Import of equipment on concessional rate of duty by newspaper printing Presses

2834. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that printers registered with the Registrar of Newspapers such as newspaper printing presses are only entitled to import equipment on concessional rates of duty;

(b) whether it is a fact newspaper printing presses do job work for outsiders; and

(c) if so, the reasons for such discrimination between commercial printers and printers registered with the Registrar of Newspapers in the matter of customs duty concession?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Yes, Sir. Certain specified machinery imported by newspaper establishments registered with the Registrar of Newspapers for India are subjected to concessional rates of import duty.

(b) These presses are not debarred from doing job work for others.

(c) Newspapers have always been allowed certain concessions because of the important role played by them in mass education and social awakening.